THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM!): (a) Yes, Sir. However, DDA has reported that all efforts are being done to maintain services and amenities at the ISBT.

(b) and (c) The Delhi Admn- has reported that an ISBT is to be set up in an area of 32.27 acres *ot* land near Nazamuddin. The land has since been purchased from Delhi Development Authority and the conceptual flan for traffic and parking of vehicles prepared by the consultant. The earth filling work and construction of boundary wall is in progress. The project is likely to be completed during the 8th Five Year Plan period, subject to the clearances from the concerned agencies/Departments.

Review of Dravida Ganga and Madras metro plans

3515. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dravida Ganga and Madras Metro plans are likely to be reviewed;

(b) whether Government propose to connect the big rivers of the North and channelise them to tide over water scarcity in south; and

(c) if so, by when the plan is likely to be finalised?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) There is no such proposal.

(b) The National Water Development Agency has taken up studies pertaining to the National Perspective Plan for Water Resources Development in India for transfer of surplus water to water short areas, involving linking Brahmaputra with Mahanadi, which in turn is proposed to be linked with Godavari-Krishna-Penner and Cauvery.

(c) The National Water Development Agency has drawn up a programme to complete all the studies including field survey and investigation by the year 2000 AD.

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी भर जाने की समस्या

3516. श्री अजीत जोगी:
श्री बेकल "उत्साही":

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी भर जाने की समस्या के समाधान हेतु 1987 के कृतिक बल के माध्यम से कितनी धनराशि मंजूर की थी ;

(ख) क्या धनराशि जारी कर दी गयी है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रयोजन के लिए प्रस्ताव में कितनी धनराशि जारी की गयी है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए उन राज्यों के अनुदानों और ऋणों में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जल जमाव की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1987 में कोई कार्यबल नहीं था । तथापि, देश में विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं में जल जमाव, लवणता क्षारीयता से प्रभावित समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वर्ष 1986 के दौरान सलाहकार (सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया था ताकि समस्याओं के समाधान के लिए उनका सुधार करने के वास्ते उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाने तथा भावी योजना आवंटनों में उचित प्राथमिकताओं का सुझाव देने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके । कार्य दल ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

3517. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं/जलाशय/बांध चालू किए हैं और किन-किन को आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है ;

(ग) किन-किन परियोजनाओं के काम में विलम्ब हो रहा है और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) निर्माण-कार्य में विलम्ब होने से लागत में किस हद तक वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ) सूचना अनुपत्र में दी गई है । (देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 81]

कृषि भूमि का कुल क्षेत्र

3518. **श्री राघवजी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में कृषि होती है और प्रत्येक राज्य में सरकारी साधनों से तथा निजी साधनों में सिंचाई सुविधा प्राप्त भू-क्षेत्र संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन राज्यों में, जहां अपेक्षाकृत कम सिंचित भूमि है परन्तु जर्मीन उपजाऊ है, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(ख) कुंओं की सिंचाई और लघु सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त देश में सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के लिए 263 वृहद सिंचाई परियोजनाएं तथा 1104 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गयी है । अब तक 83 वृहद और 777 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं ।

विवरण]

31.3.91 की स्थिति (हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	आंकी गयी सिंचाई सुविधाएं (सृजित क्षमता)	
			सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	16194	4865.41	1548.56
2.	अरुणाचल प्रदेश . .	301	59.28	0.05
3.	असम . . .	3229	618.66	174.87
4.	बिहार . . .	11195	4661.20	3904.80
5.	गोवा . . .	222	27.51	1.21
6.	गुजरात . . .	12336	1655.47	1446.12